

EDITOR'S SCATVIEW

India's cable, satellite and broadband industry is undergoing a structural transformation, driven by the convergence of connectivity, entertainment and digital technologies. SCAT Marketplace 2026 reflected this changing ecosystem, bringing together industry stakeholders to explore emerging opportunities, technological innovation and the future of digital infrastructure. Yet, beneath this optimism lies a more challenging question: how can the industry translate technological growth into sustainable commercial opportunities?

TRAI's proposed authorisation framework for Application-Based Linear Television Distribution signals an important regulatory shift. While extending regulatory parity to internet-based television is understandable, its implementation must address jurisdictional overlaps, compliance costs and commercial viability. The objective should be to encourage innovation without creating additional barriers for emerging distribution platforms or established operators.

Traditional broadcasting, meanwhile, faces mounting pressure. Declining pay DTH subscriptions and weakening private FM advertising revenue point to changing consumer preferences and growing competition from digital platforms. Cable operators, in particular, must look beyond conventional television distribution and accelerate their transition towards broadband, digital services and integrated connectivity solutions. Network modernisation and revenue diversification will be critical to their survival.

Broadcasters are also seeking greater regulatory flexibility. IBDF's opposition to the proposed public service content mandate and its demand for proportionate penalties highlight the industry's concern over excessive regulatory intervention. A predictable regulatory environment that balances public interest with commercial freedom is essential for sustained investment and growth.

Globally, the reported US$1 billion investment involving Elon Musk and the continuing realignment of media assets following Skydance's acquisition of Warner Bros Discovery underline the scale of capital and strategic ambition reshaping the entertainment business.

Taken together, these developments point to an industry at a crossroads. India's broadcasting future will not be determined by technology alone, but by the ability of stakeholders to adapt their business models, embrace convergence and engage with a regulatory framework that supports innovation, competition and long-term sustainability.

(Manoj Kumar Madhavan)

*भारत का केबल, सैटेलाइट और ब्रॉडबैंड उद्योग एक संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जो कनेक्टिविटी, मनोरंजन और डिजिटल तकनीकों के एक कन्वर्जेंस से प्रेरित है। 'स्कैट मार्केट प्लेस **2026**' ने इस बदलते इकोसिस्टम को दर्शाया, जहां उद्योग से जुड़े सभी पक्ष नये अवसरों, तकनीकी नवाचार और डिजिटल बुनियादी ढ़ांचे के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ आये। हालांकि इस सकारात्मक सोच के पीछे एक चुनौतिपूर्ण सवाल भी है: यह उद्योग तकनीकी विकास को टिकाऊ व्यावसायिक अवसरों में कैसे बदल सकता है?*

एप्लिकेशन बेस्ड लीनियर टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्राई का प्रस्तावित ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क एक महत्वपूर्ण नियामक बदलाव का संकेत देता है। इंटरनेट आधारित टेलीविजन को भी उसी तरह के नियामक दायरे में लाना समझ में आता है, लेकिन इसे लागू करते समय अधिकार क्षेत्र के टकराव, अनुपालन लागत और व्यावसायिक व्यवहार्यता जैसे मुद्दों पर ध्यान देना देना जरूरी है। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना होना चाहिए, न कि नये वितरण प्लेटफॉर्मों या पहले से स्थापित ऑपरेटरों के लिए कोई अतिरिक्त बाधा खड़ी करना।

वहीं, पारंपरिक प्रसारण पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। पेड डीटीएच सब्सक्रिप्शन में गिरावट और निजी एफएम विज्ञापन में कमी, उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं और डिजिटल प्लेटफॉर्मों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा की ओर इशारा करती है। विशेष रूप से केबल ऑपरेटरों को पारंपरिक केबल टेलीविजन से आगे बढ़कर ब्रॉडबैंड, डिजिटल सेवाओं और सबसे महत्वपूर्ण एकीकृत कनेक्टिविटी समाधानों की ओर अपने बदलाव को गति देनी होगी। नेटवर्क का आधुनिकीकरण और राजस्व विविधीकरण उनके आस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होगें।

प्रसारक अधिक रेगुलेटरी लचीलेपन की मांग कर रहे हैं। 'पब्लिक सर्विस कंटेंट' के प्रस्तावित अनिवार्य प्रावधानों का आईबीडीएफ द्वारा विरोध और आनुपातिक दंड की मांग, रेगुलेटरी मामलों में अत्याधिक दखलंदाजी को लेकर उद्योग की चिंता को दर्शाती है। लगातार निवेश और विकास के लिए एक ऐसा रेगुलेटरी माहौल जरूरी है, जो जनहित और व्यावसायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन को बनाये रखे।

*वैश्विक स्तर पर, एलन मस्क से जुड़ी **1** अरब अमेरिकी डॉलर की निवेश रिपोर्ट और स्काईडांस द्वारा वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के अधिग्रहण के बाद मीडिया संपत्तियों में हो रहे बदलाव, मनोरंजन उद्योग को नया रूप देने वाली पूंजी और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बड़े पैमाने को दर्शाता है।*

इन सभी बातों को एकसाथ देखें तो पता चलता है कि यह उद्योग एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से आगे की दिशा तय होनी है। भारत में प्रसारण का भविष्य केवल तकनीकी से तय नहीं होगा, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि इससे जुड़े पक्ष अपने बिजनेस मॉडल को कितना बदल पाते हैं और एक ऐसे नियामक ढ़ांचे के साथ कैसे काम करते हैं जो नवाचार, प्रतिस्पर्धा और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देता हो।

(Manoj Kumar Madhavan)